आज़ादी का अमृत महोत्सव

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
जो हठि राखै धर्म को, तिहिं राखै करतार

आजादी के अमृत महोत्सव

के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.

एवं

बी.एड्. विभाग

महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

के संयुक्त तत्वावधान में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका कार्यान्वयन

विषय पर आयोजित

दो दिवसीय

राष्ट्रीय संगोष्ठी

कार्तिक कृष्ण षष्ठी एवं सप्तमी, युगाब्ध-5124, वि.सं. 2079
तद्नुसार 15 एवं 16 अक्टूबर, 2022 ई.

सेवा में,

_____

_____

_____

प्रेषक :

डॉ. प्रदीप कुमार राव

प्राचार्य/अध्यक्ष, आयोजन समिति

महाराणा प्रताप महाविद्यालय

जंगल धूसड़, गोरखपुर-273 014

Website : www.mpm.edu.in

E-mail : nationalseminarnep@mpm.ac.in

परामर्शदात्री समिति

प्रो. डी.पी. सिंह	पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; शिक्षा सलाहकार, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन
प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे	पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं चेयरमैन, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच
प्रो. जे.पी. पाण्डेय	कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
प्रो. रमाशंकर दुबे	कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात
प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी	कुलपति, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक, छत्तीसगढ़
प्रो. के.एन. सिंह	कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिणी बिहार, गया, बिहार
प्रो. रजनीश शुक्ल	कुलपति, महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
डॉ. ए.के. सिंह	कुलपति, महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ.प्र.
मेजर जनरल (डॉ.) अतुल बाजपेई	कुलपति, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर
प्रो. हरिकेश सिंह	पूर्व कुलपति, सी.जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार
श्री पवन कुमार	निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.
डॉ. मजहर आसिफ	प्रोफेसर एवं डीन, स्कूल आफ लैंग्वेज लिट्रेचर एण्ड कल्चर स्टडीज, जे.एन.यू., नई दिल्ली
प्रो. हरि बहादुर श्रीवास्तव	कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उ.प्र.
प्रो. सुभाष अग्रवाल	पूर्व अध्यक्ष एवं डीन, सी.एस.जी.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर
प्रो. पी.एन. सिंह	निदेशक, इण्टर यूनिवर्सिटी सेन्टर फॉर टीचर एजुकेशन, बी.एच.यू.
प्रो. पूनम टण्डन	फिजिक्स विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रो. पी.के. मिश्रा	नेशनल इंस्टीच्यूट आफ् एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली
प्रो. हरिशंकर सिंह	अध्यक्ष एवं डीन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.
प्रो. मधुसूदन जे.बी.	अध्यक्ष, एजुकेशन एण्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
प्रो. आशीष श्रीवास्तव	डीन, फैकल्टी आफ एजुकेशन, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार
प्रो. के.के. चौधरी	अध्यक्ष एवं डीन, सेन्ट्रल विश्वविद्यालय, गया, बिहार
प्रो. विशाल सूद	शिक्षाशास्त्र विभाग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमांचल
प्रो. शंकर शरण	प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
डॉ. वी. रामानाथन	आचार्य, आई.आई.टी., बी.एच.यू., वाराणसी, उ.प्र.
प्रो. शोभा गौड़	अध्यक्ष एवं डीन, शिक्षा संकाय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. रामानन्द	निदेशक, सेंटर फार पालिसी रिसर्च एण्ड गर्वनेंस, नई दिल्ली
प्रो. मधुसुदन जोशी	एच.सी.यू., हैदराबाद
प्रो. रजनी रंजन सिंह	विभागाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र, शकुन्तला मिश्रा रेहेबिटेशन विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रो. ज्ञानेन्द्र नाथ तिवारी	आचार्य बी.एड्. विभाग, नागालैण्ड सेन्ट्रल विश्वविद्यालय, कोहिमा
डॉ. राजशरण शाही	शिक्षाशास्त्र विभाग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

आयोजन समिति

मुख्य संरक्षक

पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज
मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन
प्रबन्धक, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

संरक्षक

प्रो. उदय प्रताप सिंह
अध्यक्ष, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर
पूर्व कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उ.प्र.

प्रो. राजेश सिंह
कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ.प्र.

प्रो. सदानन्द प्रसाद गुप्त
कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.

अध्यक्ष

डॉ. प्रदीप कुमार राव
प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

संयोजक/सचिव

शिप्रा सिंह
बी.एड्. विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर

सदस्य

डॉ. विजय चौधरी	डॉ. आरती सिंह
डॉ. सुबोध कुमार मिश्र	श्रीमती पुष्पा निषाद
डॉ. मंजेश्वर	सुश्री दीप्ति गुप्ता
डॉ. अभिषेक सिंह	डॉ. अनुभा श्रीवास्तव
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	श्रीमती विभा सिंह
श्री जितेन्द्र कुमार प्रजापति	श्री रमाकान्त दूबे
डॉ. वेंकट रमन पाण्डेय	डॉ. हनुमान प्रसाद उपाध्याय
श्रीमती साधना सिंह	डॉ. शालू श्रीवास्तव
डॉ. नीलम गुप्ता	डॉ. सुधा शुक्ला
डॉ. अमित कुमार त्रिपाठी	श्री हरिकेश यादव
सुश्री स्मिता दूबे	सुश्री रितिका त्रिपाठी
सुश्री शारदा रानी	श्री अरविन्द कुमार मौर्य
श्री अभिषेक त्रिपाठी	डॉ. सत्येन्द्र नाथ शुक्ल
सुश्री श्रद्धा सिंह	

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
जो हठि राखै धर्म को, तिहिं राखै करतार

आजादी के अमृत महोत्सव
के अन्तर्गत
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.
एवं
बी.एड्. विभाग
महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर
के संयुक्त तत्वावधान में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका कार्यान्वयन

विषय पर आयोजित
दो दिवसीय

राष्ट्रीय संगोष्ठी

कार्तिक कृष्ण षष्ठी एवं सप्तमी, युगाब्ध-5124, वि.सं. 2079
तद्नुसार 15 एवं 16 अक्टूबर, 2022 ई.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

महाराणा प्रताप महाविद्यालय

जंगल धूसड़ - गोरखपुर
नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी ''बी''

Website : www.mpm.edu.in
E-mail : nationalseminarnep@mpm.ac.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका कार्यान्वयन

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में कुछ अपने ढंग से सोचना शुरू किया। प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया आरम्भ हुई, शिक्षा के क्षेत्र में भी। इस सन्दर्भ में भारत सरकार का पहला बड़ा कदम था विश्वविद्यालय आयोग (राधाकृष्णन आयोग) का गठन। आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रशासन, संगठन और उसके स्तर को ऊँचा उठाने सम्बन्धी अनेक ठोस सुझाव दिए। कुछ सुझावों का कार्यान्वयन भी किया गया; परन्तु वह सब हाथ नहीं लगा, जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे। इस आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक है, कि उसके पूर्व की माध्यमिक स्तर की शिक्षा को ऊँचा उठाया जाए जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने मुदालियर आयोग के सुझावों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन करना भी शुरू किया, परन्तु इससे भी हम वह लक्ष्य न प्राप्त कर सके, जो शिक्षा से प्राप्त करना था। अतः भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने–समझने और देशभर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से शिक्षा आयोग का गठन 1964 में किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना गया। शिक्षा आयोग (1964–66) ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का भुभारम्भ किया, उसके आधार पर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विशय माना गया। कोठारी आयोग की संस्तुति के आधार पर राष्ट्र में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सम्मुख प्रस्तुत की गई। सभी स्तर की शिक्षा के प्रसार में कुछ तेजी आई और उसके उन्नयन की ओर कदम बढ़े, किन्तु संसाधनों एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में इस नीति का ईमानदारी से पालन नहीं किया जा सका। यह नीति भी राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। लगभग दो दशक बाद 1986 में एक बार पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में भी तत्कालीन शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव अधिक थे और नीति सम्बन्धी घोषणाएँ कम थीं। नीति सम्बन्धी जो घोषणाएँ की भी गई, उनका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से न हो सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के कार्यान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। केन्द्र सरकार ने 3 वर्ष बाद, 1990 में इसकी समीक्षा हेतु 'राममूर्ति समीक्षा समिति' का गठन किया। अभी इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी शुरू नहीं हुआ था कि केन्द्र की नई सरकार ने 1992 में इस नीति के कार्यान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा हेतु 'जर्नादन रेड्डी समिति 1992' का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों की आख्याओं के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन कर दिए और इसे 'संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986' के नाम से प्रकाशित किया। सरकार ने उसी वर्ष इसकी कार्ययोजना में भी कुछ परिवर्तन किये। इस परिवर्तित कार्ययोजना को 'प्लान ऑफ एक्शन 1992' कहा गया। इसमें भी कोई विशेष संशोधन नहीं किये गये, केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को विस्तार भर दिया गया है।

सन् 1986 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद भारत में 34 वर्षों के बाद भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आयी है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बनाये रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ–साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या–समाधान सम्बन्धी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

इस राष्ट्रीय शिक्षा का दृष्टिकोण भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविद् छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। वस्तुतः 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' नए युग के नए भारत की आधारशिला है। यह शिक्षा नीति आजाद भारत में सांस्कृतिक भारत की पुनर्प्रतिश्ठा का उद्घोष है।

किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसे कार्यान्वयन के लिए, कई निकायों द्वारा समन्वित एवं व्यवस्थित तरीके से बहुत सी पहल करनी होगी और कई कदम उठाने की जरूरत होगी जिससे बाधा रहित संचालन हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों को सम्पूर्णता की ओर अग्रसर करने एवं तथ्यों पर विचार–विमर्श करने हेतु उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ के वित्तीय एवं अकादमिक सहयोग से महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर ने ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं उसके कार्यान्वयन के आयाम'' विषय पर 15–16 अक्टूबर 2022 को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कराने का निर्णय लिया है। इसमें शोधार्थी संगोष्ठी के विविध आयामों के किसी भी विषय/शीर्षक पर अपना शोध–पत्र दे सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त विषय को निम्न उप–विषयों/उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा एवं उसका कार्यान्वयन।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा प्रणाली एवं उसका कार्यान्वयन।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं उसका कार्यान्वयन।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम संरचना।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शिक्षक–विद्यार्थी की भूमिका।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयी शिक्षा का स्वरूप एवं उसका कार्यान्वयन।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण एवं उसका कार्यान्वयन।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा एवं कार्यान्वयन।
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा एवं कार्यान्वयन।
11. स्वास्थ्य शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
12. तकनीकी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक प्रशासन और प्रबन्धन।
14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय संस्कृति।
15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक तकनीकि एवं डिजिटल शिक्षा।
16. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दूरस्थ शिक्षा।
17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यांकन प्रविधि।
18. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध।
19. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा।
20. भारत के पुनर्निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका।
21. भारत की वैश्विक भूमिका और राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

शोध–प्रपत्र

संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध–प्रपत्र/आलेख में विषय वस्तु का उद्देश्य, सार–संक्षेप, बीज शब्द, प्रयुक्त विधितन्त्र एवं निष्कर्ष का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सूचना प्रपत्र में निर्दिष्ट विषयों की सीमा में ही शोध–प्रपत्र स्वीकृत किये जायेंगे। शोध–पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में स्वीकृत होंगे। शोध–पत्र/आलेख लगभग 2500 शब्दों में होना चाहिए तथा 30 सितम्बर 2022 तक ई–मेल nationalseminarnep@mpm.ac.in पर पहुँच जाना चाहिए। प्राप्त शोध पत्र/आलेखों का प्रकाशन संगोष्ठी के पूर्व ही करने की योजना है। शोध–पत्र ए–4 आकार के कागज पर कम्पोज होना चाहिए। हिन्दी भाषा के शोध–पत्र वॉकमैन चाणक्या प्रारूप में फॉन्ट साइज 14 में तथा अंग्रेजी भाषा के शोध–पत्र टाइम्स न्यू रोमन प्रारूप में फॉन्ट साइज 12 में होने चाहिए।

पंजीयन

पंजीयन शुल्क शोधार्थियों हेतु रू. 500/– तथा प्राध्यापकों हेतु रू. 700/– निर्धारित है। आमंत्रित अतिथियों/विषय–विशेषज्ञों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में **'प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़'** के नाम से अथवा नकद संगोष्ठी के समय पंजीकरण के दौरान देय अनुमन्य होगा।

यात्रा/आवास/भोजन–व्यवस्था

आमंत्रित अतिथियों एवं विषय विशेषज्ञों को उनके आने–जाने का व्यय आयोजन समिति द्वारा देय होगा। सभी के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आयोजकों की ओर से निःशुल्क रहेगी किन्तु आने की पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

गोरखपुर

गोरखपुर महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है। यह नगर उत्तर–पूर्व रेलवे का मुख्यालय होने के कारण देश के लगभग सभी शिक्षा केन्द्रों/महानगरों से रेल, सड़क तथा वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। नगर के पार्श्व में अनेक दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। भगवान बुद्ध का गृहनगर कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित वर्तमान पिपहरवा) यहाँ से लगभग 90 किमी. की दूरी पर है। गोरखपुर नगर से भगवान बुद्ध की निर्वाण–स्थली कुशीनगर 50 किमी. की दूरी पर स्थित है। मध्ययुगीन सन्त एवं समाज सुधारक तथा हिन्दू–मुस्लिम एकता के पोषक सन्त कबीर की निर्वाण स्थली मगहर यहाँ से 20 किमी. दूरी पर स्थित है। यहाँ से नेपाल सीमा की दूरी लगभग 100 किमी. है। नेपाल के दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए सड़क–मार्ग से सुगमतापूर्वक जाया जा सकता है। काठमाण्डु गोरखपुर से 400 किमी. की दूरी पर है। इन समस्त स्थलों की यात्रा बस अथवा टैक्सी द्वारा सरलतापूर्वक की जा सकती है। नगर–क्षेत्र में भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें गोरखनाथ–मंदिर, गीता वाटिका, गीता प्रेस, विष्णु मंदिर आदि प्रमुख हैं। सितम्बर माह में गोरखपुर का मौसम वर्षा से परिपूर्ण एवं आर्द्र रहता है। तापमान सामान्य बना रहता है।